भारत में ग्रामीण गरीबी–समस्या एवं समाधान

* डॉ. प्रमोद भारतीय

भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण की धीमी प्रगति एवं द्रीव गति से बढती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न श्रमशक्ति को रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जा सका है । देश में बेकार पडी श्रम शक्ति को रोजगार कृषि एवं संबद्ध उद्योगों में ही उपलब्ध हो सकता है । अतः देश की आर्थिक प्रगति एवं बेराजगारी दूर करने हेतु कृषि के विकास का बडा महत्त्व है इसे स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **कोल एवं हूबर ने कहा है कि**–''सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये कृषि का विकास पहले होना चाहिये और यदि किसी क्षेत्र के अविकसित होने से दूसरे क्षेत्र के विकास में बाधा पडती है, तो वह अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा जो अन्य क्षेत्रों के विकास को बाधित करेगा ।'' **प्रो. शुल्ट्ज के अनुसार**–''कोई भी अल्पविकसित राष्ट्र खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त किए बिना आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकता है ।'' भारत गॉवों का देश है । यहॉ के कुल 6,38,588 गॉवों में देश की लगभग 72.2 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है । यहॉ की जनसंख्या में 31.7 प्रतिशत कृषक तथा शेष कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत है । भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । और आज भी वह महत्त्वपूर्ण है । विगत तीन दशको से भी अधिक अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में हुए संगठित प्रयास के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है । देश के उद्योग धन्धे विदेशी व्यापार–विदेशी मुद्रा अर्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता यहॉ तक कि राजनैतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर करता है।

गरीबी की समस्या :– अधिकाशं पिछड़े एवं विकासशील देशों में न्यून आय–स्तर के कारण जनसंख्या के एक बडे भाग का जीवन स्तर बहुत नीचा है। इस वर्ग के दो समय का भोजन एवं जीवन की अन्य जरूरी वस्तुएं भी प्राप्त नहीं हो पाती । **इस प्रकार**–''गरीबी से अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताओं खाना, कपडा, स्वास्थ्य आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है।'' दूसरे शब्दों में – ''गरीबी या निर्धनता से अर्थ उस न्यून आय से है, जिसकी एक परिवार के लिये आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकतता होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है ।'' **रेगरन नर्क्स** संभवतया पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होने गरीबी की व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास किया है । उन्होने गरीबी शब्द का प्रयोग अल्प विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में उसकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में किया है । **उनका प्रचलित कथन कि** '' एक देश इसलिए निर्धन है क्योकिं वह निर्धन है ।'' अर्थात निर्धनता अपनी जननी स्वयं है, निर्धनता का कारण और परिणाम स्वयं निर्धनता ही है । इसी आधार पर नवर्स ने ''गरीबी के दुष्चक्र'' की विवेचना की है ।

भारत में गरीबी की समस्याः–भारत में आय वितरण की असमानताओं के जो तथ्य प्रकट होते है, उनसे जनसाधारण की घोर गरीबी का चित्र उभरकर सामने आता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में आर्थिक विकास हुआ है, तकनीकी प्रगति हुई है , परन्तु जनसाधारण के ऊपर उसका बहुत असर पडा है । देश में गरीबी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। देश को राजनैतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन जब तक आर्थिक स्वतंत्रता और लौगों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं आता, इस स्वतंत्रता का महत्त्व स्वतः कम हो जाता है । अतः इस समस्या का समाधान अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। नौवी पंचवर्षीय योजना में यह आशा व्यक्त की गई कि देश में निर्धनता अनुपात जो 1996–97 में 29.2 प्रतिशत था, घटकर 2001–02 में लगभग 18 प्रतिशत ,2006–07 में 9.5 प्रतिशत तथा 2011–12 में और अधिक घटकर 4.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहूँच जाएगा। इस अवधि में अति निर्धन लोगों की संख्या में भी प्रभावी रूप से कभी होने की संभावना है।

भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण :– गरीबी रेखा के नीचे रह रही जनसंख्या की यह प्रवृति ग्रामीण एवं शहरी दौनों क्षेत्रों में है । यह समस्या शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है । इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की समस्या अत्यधिक दयनीय है । गरीबी की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक भयावह है । ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे रह रहा , के संदर्भ में निम्न तथ्य महत्त्वपूर्ण है – (1) खेतिहर मजदूर जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, का लगभग 60 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है । (2) खेतिहर मजदूर जिनके पास बहुत थोडी सी भूमि है, का लगभग भाग 40 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है । (3) गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में ग्रामीण दस्तकारों का वर्ग भी शामिल है । (4) इस वर्ग में वे कृषक भी सम्मिलित है । जिनके पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि है ।

''भारत में सबसे अधिक गरीबी उड़ीसा राज्य में है, जहाँ कि 47.15 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है । इसके बाद बिहार का स्थान हैं जहाँ पर यह प्रतिशत 42.6 है। तीसरा स्थान मध्यप्रदेश राज्य का है, जहाँ गरीबी का प्रतिशत 37.43 है। अन्य राज्यों का प्रतिशत इस प्रकार है। उत्तरप्रदेश 31.15, तमिलनाडू 21.12 प्रतिशत, कर्नाटक 20.4 प्रतिशत, महाराष्ट्र 25.02 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल 27.02 प्रतिशत व राजस्थान 15. 28 प्रतिशत।'' जहाँ तक गिनती का प्रश्न है उत्तरप्रदेश में गरीबी की संख्या सबसे अधिक है । इस राज्य में 5.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते है, जबकि बिहार का दूसरा स्थान है। यहॉ 4.3 करोड़ व्यक्ति इस श्रेणी में माने जाते है।

*** सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ (म.प्र.)**

मध्यप्रदेश में 3 करोड़, महाराष्ट्र में 2.2 करोड़, पश्चिम बंगाल में 2.1 करोड़, उड़िसा में 1.7 करोड व आन्ध्र में 1.2 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे ऑके गए है। अप्रैल 2002 में योजना आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम हो रही है परन्तु उसकी गति धीमी है? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व उड़ीसा आदि राज्यों की आधी या इससे अधिक जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रही है। हाल ही में विश्व बैंक के गरीबी एवं मानव संसाधन प्रभाग ने भारत में गरीबी के अनुमान प्रकाशित किए है। इस अनुमान के अनुसार 1950–51 से 1973–74 के मध्य गरीबी की व्यापकता के विषय में कोई दीर्घकालीन प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती, किन्तु इसके इसके बाद 1973–74 में 1989–90 तक गरीबी की व्यापकता में क्रमशः कमी हुई है, नब्बे के दशक में शुरू के वर्षो में गरीबी बढ़ी है और इन अनुमानों के अनुसार 1992 में ग्रामीण क्षेत्र में 43.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 33.7 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी।

जनसंख्या की कृषि पर निर्भरताः–भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता से भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होता है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता फसली क्षेत्र कम होता जाता है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहती है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत जनसंख्या का 60.0 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर था, जबकि अन्य विकासशील देशों में यह प्रतिशत 40 से 90 है। इसके विपरीत विकसित देशों में यह प्रतिशत 2 से 4 है।

भारत में गरीबी के कारणः–पिछड़े एवं विकासशील देशों में पूँजी के अभाव के कारण उपलब्ध जनशक्ति को उत्पादक कार्यो में लगाना संभव नहीं होता । इससे बरोजगारी की समस्या पैदा होती है । बेरोजगारी के कारण श्रमिकों की आय कम हो जाती है और उन्हे गरीबी की जिन्दगी के लिये विवश होना पड़ता है । बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है।

भारत में गरीबी के निम्न कारण हैः–(1) जनसंख्या में वृद्धि (2) बेरोजगारी में वृद्धि (3) कार्यशील जोतों को छोटा होना (4) खाद्य पदार्थो की कीमतों में वृद्धि (5) सामाजिक पिछड़ापन श्रम की गतिशीलता में बाधाऐं (6) कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि व निर्धनता (7) भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी (8) हरित क्रांति व ग्रामीण निर्धनता (9) रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि (10) निम्न आय अर्जक परिसम्पत्तियॉ (11) कमाई या अर्जन का निम्न स्तर (12) दोषपूर्ण विकास रणनीति (13) अपर्याप्त अन्तरण (14) मुद्राप्रसार (15) सामाजिक कारण ।

गरीबी को दूर करने हेतु सुझाव–गरीबी की समस्या का मूल समाधान गरीब व्यक्तियों की आय वृद्धि में निहित है । अतः उन उपायों कों क्रियान्वित करना होगा जो निर्धन व्यक्तियों की आय वृद्धि में सहायक बन सके। भारत में गरीबी कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकते है–(1) आर्थिक विकास की गति को तेज करना (2) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास (3) संरचनात्मक सुधार (4) कृषि विकास (5) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्य (6) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना (7) जनसंख्या नियत्रंण (8) ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण कार्य (9) गहन कृषि विकास व भूमि सुधार (10) राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (11) ग्रामीण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (12) ग्रामोत्थान की व्यापक योजना।

इस तरह देश में गरीबी दूर करना तथा बरोजगारी की समस्या से निजात पाना एक चुनौती भरा कार्य है । इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिये सघन आर्थिक एवं सामाजिक प्रयास तथा दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की स्थिति सुधारने के लिये ''विजन 2020 फॉर इण्डिया'' नाम से एक महत्त्वकांक्षी नीतिगत दस्तावेज केन्द्र द्वारा तैयार किया जा रहा है । इसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्थिति में सुधार करना है ताकि अगले 20 वर्षों में ''गरीबी रेखा से नीचे'' का कलंक पूर्णतः मिटाया जा सके।

निर्धनता की स्थिति के आकलन के लिये 2004–05 के अपने सर्वेक्षण में दो तरह की प्रश्नावली का इस्तेमाल किया है । उनमें उक 30 दिन के यूनी फार्म रिकॉल पीरिएड (URP) उपभोग व्यय पर व दूसरा 365 दिन के संदर्भ वाले मिक्स्ड रिकॉल पीरिएड (MRP) पर आधारित था इन दोनों ही आधारों पर निर्धनता अनुपात अलग–अलग ऑकलित किया गया है। यू.आर.पी. आधारित ऑकलन में देश में निर्धनों की संख्या 2004–05 में 30.7 करोड़ बताई गई है, जबकि एम.आर.पी. ऑकड़ों में यह 23.85 करोड़ है, इसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्धनता की कुल संख्या क्रमशः 17.03 करोड़ व 6.82 करोड़ ऑकलित है , इससे पूर्व 1999–2000 के ऑकड़ो में देश के निर्धनों की कुल संख्या (निर्धनता रेखा से नीचे कुल जनसंख्या) 26.02 करोड़ (ग्रामीण क्षेत्रों में 19.32 करोड़ व शहरी क्षत्रों में 6.7 करोड़) थी । ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण संरचना के विकास हेतु हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना भारत निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भी प्रतिबद्ध है। भारत के **राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने इस योजना का समर्थन करते हुए इसका वर्णन किया कि ये ''वो मंच है जिस पर मेंरी सरकार, ग्रामीण भारत के लिये अपने नए प्रस्ताव का निर्माण करेगी । ''**प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह** ने प्रशंसा की कि ''भारत निर्माण अगले चार वर्षो के लिये ग्रामीण संरचना में कार्य के लिये एक समयबद्ध कारोबार–योजना होगी, भारत निर्माण के अन्तर्गत, सिचांई, सड़के, ग्रामीण दूर संचार संयोजन के क्षेत्रों में कार्य प्रस्तावित है । इन ध्येयों में से प्रत्येक के अन्तर्गत हमने साधित होने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए है, ताकि इस पहल में प्रगति की जवाबदेही हो।''

इस तरह भारत निर्माण को ग्रामीण भारत की वृद्धि संभाव्यता के रास्ते खोलने का प्रयास और एक नए युग के स्वागत की चाभी के रूप में देखा जा रहा है ।

तालिका क्रं. 1:1

भारत में राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात का प्रक्षेपण (प्रति. में)

क्षेत्र	1996–97	2001–02	2006–07	2011–12
ग्रामीण	30.55	18.61	9.64	4.31
नगरीय	25.58	46.46	9.28	4.49
कुल	29.18	17.98	9.53	4.37

तालिका क्रं. 1:4

भारत में ग्रामीण जनसंख्या

जनगणना वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या (दस लाख में)	ग्रमीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
1901	213	89.2
1911	226	89.7
1921	223	88.8
1931	246	88.0
1941	275	86.1
1951	299	82.7
1961	360	82.0
1971	439	80.1
1981	524	76.7
1991	629	74.3
2001	743	72.2

इण्डिया विजन–2020 के महत्वपूर्ण लक्ष्य

क्रं.	विकास के सूचक	2000–01की स्थिति	2020 की संभावना
1.	गरीबी रेखा से नीचे की आबादी (प्रति.में)	26 प्रतिशत	13 प्रतिशत
2.	बेरोजगारी की दर	7.3 प्रतिशत	6.8 प्रतिशत
3.	कृषि में रोजगार	56 प्रतिशत	40 प्रतिशत

तालिका क्रं. 1:3

भारत में निर्धनों की संख्या व निर्धनता अनुपात

वर्ष	निर्धन जनसंख्या (करोड़)			निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)		
	अखिल भारत	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत	ग्रामीण	शहरी
1993–94	32.03	24.40	7.63	36.0	37.3	32.4
2004–05	30.17	22.09	8.08	27.5	28.3	25.7
यू. आर.पी. आधारित ऑकड़े						
1999–02	26.02	19.32	6.70	26.1	27.1	23.6
2004–05	23.85	17.03	6.82	21.8	21.8	21.7

तालिका क्रं. 1:2

भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या (करोड़ में)

वर्ष	कृषि श्रमिक	कृषक	अन्य व्यवसाय में कार्यरत	कुल जनसंख्या
जनगणना–1951	2.75	6.98	4.22	13.95
	(19.7)	(50.0)	(30.3)	(100.00)
जनगणना–1961	3.15	9.96	5.76	18.87
	(16.7)	(52.8)	(30.5)	(100.00)
जनगणना–1971	4.75	7.83	5.47	18.05
	(26.3)	(43.4)	(30.3)	(100.00)
जनगणना–1981	5.55	9.25	7.45	22.25
	(24.9)	(41.6)	(33.5)	(100.00)
जनगणना–1991	7.46	11.6	10.0	28.54
	(26.1)	(38.8)	(35.1)	(100.00)
जनगणना–2001	10.7	12.8	16.7	40.2
	(27.0)	(32.0)	(41.0)	(100.00)

सन्दर्भ-

1. डॉ. ओ.पी. शर्मा भारतीय अर्थव्यवस्था –नई शताब्दी में
2. डॉ. झुनझुन वाला भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षात्मक अध्ययन
3. डॉ. पी.डी. माहेश्वरी भारतीय आर्थिक नीति
   डॉ. शीलचन्द्र गुप्ता
4. डॉ. जयप्रकाश मिश्र कृषि अर्थशास्त्र
5. डॉ. पी.डी. माहेश्वरी भारत में आर्थिक पर्यावरण
   डॉ. शीलचन्द्र गुप्ता
6. कद्रदत, के.पी.एम. सुन्दरम भारतीय अर्थव्यवस्था
7. भारत 2007 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
8. प्रतियोगिता दर्पण, समसामायिक वार्षिकी 2007
9. प्रतियोगिता निर्देशिका यादें – 2008
10. इको नाभिक सर्वे वर्ष 1951 से 2001 तक
11. आर्थिक समीक्षा वर्ष 2005–06